राज्यों को केन्द्रीय योजनाओं का अन्तरण

1724. श्री अजीत जोगी :
कुमारी आलिथा :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री 19 दिसंबर, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 3280 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें राज्य सरकारों को पूर्ण रूप से अंतरित किये जाने का विचार है और इसके वित्तीय निहितार्थ क्या हैं;

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन रहेंगी;

(ग) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऊपर उल्लिखित श्रेणी की कौन कौन सी योजनायें चल रही हैं; और

(घ) इस अभियान के उद्देश्य क्या हैं और इसके वित्तीय निहितार्थ क्या है तथा इससे राज्य को किस प्रकार का लाभ होगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद (एन डी सी) ने 23 और 24 दिसम्बर, 1991 को हुई अपनी बैठक में, अन्य मतों के साथ-साथ, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (नरसिंह राव समिति) से सम्बद्ध राष्ट्रीय विकास परिषद समिति की रिपोर्ट पर विचार किया था जिसमें 125 ऐसी योजनाओं को रखने और 113 योजनाओं को राज्यों को हस्तांतरण करने की सिफारिश की गई थी। यह निर्णय लिया गया था कि 113 योजनाओं को जिन्हें 1987 की रिपोर्ट को लिखते समय कार्यान्वित किया जा रहा था, केन्द्रीय निधि अंश सहित राज्यों को हस्तांतरित किया जाए जिन्हें आठवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता के फार्मूले से बाहर विमोचित किया जायेगा।

राष्ट्रीय विकास परिषद के उपरोक्त निर्णय के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि 1991-92 स्तर पर केन्द्रीय निधि अंश सहित 1992-93 में इन योजनाओं को राज्यों को हस्तांतरित कर दिया जाए। इस सम्बन्ध में वित्तीय निहितार्थों का पता केवल तभी चलेगा जब इसको अंतिम रूप दे दिया जायेगा और केन्द्रीय बजट पारित होने के पश्चात मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रभावित निधियों का हस्तांतरण कर दिया जायेगा।

(ख) भारत सरकार द्वारा रखी गई 125 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (जो नरसिंह राव समिति की रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के समय विद्यमान थी) की एक सूची संलग्न है [देखिए परिशिष्ट. 162, अनुपत्र संख्या 42]।

(ग) ऐसी योजनाओं के राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) राज्यों को इन योजनाओं का हस्तांतरण, विकासात्मक योजनाओं की क्रियान्विति में राज्यों को और अधिक लचीलापन प्रदान करते हुए आयोजना में बढ़ते हुए विकेन्द्रीकरण हेतु आठवीं योजना नीति के अनरूप है।

Setting up of working group on Housing

1725. KUMARI CHANDRIKA PREMJI KENIA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a Working Group on Hou-sing;

(b) if so, what are its terms of reference and composition; and

(c) by when it is expected to submit its report?